दोनों युनिट्स के बारे में अपने सुझाव दिये हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही न करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए क्या नई विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई जिनके कारण अब नई कमेटी की स्थापना की गई है?

SHRI MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, apart from the Administrative Reforms Commission, there were several other committees. Early in the 1980's, there was a Committee under Mr. Era Sezhiyan which went into the structure of the Life Insurance Corporation, which recommended—if I remember correctly—a splitting of the Life Insurance Corporation. Well, Government did not accept those recommendations. But certain additional powers were given. Power was given to the Zonal Offices by way of decentralisation. Since then a lot of other developments have taken place. The whole financial system of our country is faced with new challenges. The banking system, the capital markets and the insurance industry are the three major players of the financial system. I think in the light of the challenges that have taken place all over the world in the technology of work, in market practices, it is essential to ensure that India's financial sector including banking and insurance is brought up to date so that it can become fully competitive. That was the reason why this committee was appointed.

SIDBI Proposal to set up rural Industries in Gujarat

*206. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE†:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Small-Scale Industries Development Bank of India has formulated any project to set up rural industries in Gujarat State; and

(b) if so, what are the details thereof, district-wise?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Anantray Devshanker Dave.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) एक विवरण सभी पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गुजरात में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए भारतीय लघु उद्योग बैंक के प्रस्ताव

(क) और (ख): भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को सहायता उपलब्ध कराता है। सिडबी ने पिछले 3 वर्षों के अपने परिचालन के दौरान गुजरात में लघु उद्योगों को कुल 1168.11 करोड रुपए की सहायता मंजूर की है। इस सहायता से राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं।

सिडबी ने गुजरात में कई उन्नयनकारी कार्यकलाप भी शुरू किए है जैसे (i) ग्रामीण उद्यमवृत्ति वित्त कार्यक्रम, (ii) ऋण आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्तापना के लिए सहायता, (iii) कच्छ क्षेत्र में पहचान किए गए नमक और नमक पर आधारित उद्योगों के तकनीकी उन्नयन हेतु विशेष कार्यक्रम, (IV) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम और (V) ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य गैर-तकनीकी स्नातकों के लिए लघु उद्योगों हेतु प्रबंध सहायता विकास कार्यक्रम।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा है, उसमें जो बात कही गयी है उसमें यह कहा गया है कि

An assistance of Rs. 1168.11 crores was given to the small scale industries in Gujarat for employment opportunities in the rural as well as the tribal areas.

मेरा सवाल पहले से ही यह था कि रूरल एरिया में आपने कितने, यह जो आपने रकम बताई है, आप सिम्पली बता दीजिये, अमाउंट कि कितना खर्चा स्माल स्केल इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री में पर्टिकयुलरली गुजरात में हुआ ?

डा. अबरार अहमद : सर, मैं सवाल पूरा नहीं सुन पाया, दुबारा कह दें।

श्री अनन्तराय देवशंकर द्रवे : जो आपने सभा पटल पर स्टेटमेंट रखा है, उसमें मैं चाहता था कि आप पूरा विवरण देते । मेरा सवाल यह था कि रूरल एरियाज में आपने कितना खर्चा किये और यह भी बतलाइये कि रूरल एरियाज में इम्पलाईमेंट अपार्च्युनेटी के लिये आपने कितना अमाउन्ट दिया ?

डा. अबरार अहमद : सर, सिडबी की जो कार्य-प्रणाली है, सिडबी के माध्यम से जो सहायता दी जाती है, वह खासतौर से स्माल स्केल इंडस्ट्री में दी जाती है । गुजरात में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिये जो अभी तक दिया गया है उसमें जो परसन्टेज-वाइज है, गुजरात को 1990–91 के अंदर जो सेंक्शन किया वह 12....

श्री अनन्तराय देवशंकर द्रवे: मैंने यह सवाल नहीं पूछा....(**व्यवधान**)...

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: What amount has he given in the rural areas?

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं हिन्दी में बता देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में....(**व्यवधान**)...

डा. अबरार अहमद : नहीं, जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह मैं पूरी तरह से समझ गया हूं । लेकिन मुझे जो....

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : लेकिन बताना नहीं चाहते हैं ।

डा. अबरार अहमद : नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । लेकिन अभी मेरे पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अलग से ब्रेक-अप नहीं है । इसलिये टोटल में माननीय सदस्य को बता रहा था । जो कुछ उन्होंने....

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Please look at the heading of the question. It says: "Proposal to set up rural industries in Gujarat." (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Can the Minister find out the information and send it to the Member?

DR. ABRAR AHMED: Yes, Sir.

मैं उस चीज को समझ गया हूं । मैं उसको स्वीकार रह रहा हूं । लेकिन इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अलग ब्रेक-अप नहीं है ।..... (**व्यवधान**).. माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा है । मेरे पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अलग से ब्रेक-अप नहीं है। इसलिये मैं उनको बता रहा हूं कि यदि ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध हुए तो मैं माननीय सदस्य को आंकड़े भिजवा दूंगा ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम है । इसलिये अलग से बताने में शर्म अनुभव कर रहे हैं ।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, this happened on last Thursday. I would request you to look at the question. The question says: "Whether the Small Scale Industries Development Bank of India

has formulated any project to set up rural industries in Gujarat and if so, what are the details districtwise? The basic question sent is about the rural sector. So he has got a notice of ten days. After ten days, he says that he does not have a break-up. He should have got the break-up when he received the notice. (*Interruptions*) There is no supplementary in it. (*Interruptions*)

डा. अबरार अहमद : सर, वैसे सिडबी की जो ज्यादातर योजनायें हैं, ज्यादातर जो लोनिंग है वह रूरल एरियाज में हैं। फिर भी माननीय सदस्य स्पेसिफिक चाहते हैं लेकिन अभी ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है । यदि.... (**व्यवधान**)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: They do not do their home work. They do not read even the question. (*Interruptions*) We want it and that is why we sent the notice. (*Interruptions*)

डा. अबरार अहमद : मैंने कहा है कि सिडबी की ज्यादातर जो योजनायें हैं, जो भी ऋण है, वह ग्रामीण क्षेत्र के लिये है । लेकिन इस वक्त मेरे पास ब्रेक-अप नहीं है । मैं उसका पता करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।..... (**व्यवधान**)....

श्री प्रमोद महाजन : ये समझते हैं कि मेहरबानी है ।

डा. अबरार अहमद : इसमें जो ऋण दिया जाता है वह ज्यादातर रूरल क्षेत्र के लिये है ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, I think the Member has a very valid point. You please now rectify it by sending information about the rural industries.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि Special programme for Technology Upgradation of the salt based industries identified in Kutch region.

मैं यह जानना चहाता हूं कि यह जो स्पेशल प्रोग्राम फार टैक्नोलाजी है तो यह स्पेशल प्रोग्राम क्या है और मेरे क्वेश्चन का (ख) पार्ट यह है कि जो साल्ट इंडस्ट्री जयपुर में लगी हुई है उसको क्या आप कच्छ में ले आयेंगें, क्या आप यह आश्वासन देंगे और यह स्पेशल प्रोग्राम क्या है यह बता दें ?

डा. अबरार अहमद : सर, गुजरात राज्य में सिडबी द्वारा कई विकास के कार्यों में योगदान दिया गया है । इस में जो माननीय सदस्य ने नमक के बारे में पूछा है, वह उसमें से एक है और इसमें जो वहां विकास कार्य किये गये हैं उसके अंतर लघु उद्योग के लिये जो ऋण मांगा जाता है, खासतौर से नमक के क्षेत्र में, उसके लिये वहां यह योजना बनाई गई है । यही गुजरात के लिये एक योजना नहीं है बल्कि वहां 6–7 योजनायें हैं जिनमें सिडबी विशष रूप से योगदान दे रही है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था कि स्पेशल प्रोग्राम क्या है वह बता दें और स्पेशल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिये आपने क्या किया है ?

डा. अबरार अहमद : स्पेशल का मतलब यह नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 6–7 प्रोग्राम सिडबी द्वारा उसके लिये चलाये गये हैं । 6–7 तरीकों से सिडबी द्वारा योगदान दिया गया है । इसमें नमक क्षेत्र के लिये दिया गया है। यह उसमें से एक है । वैसे बहुत सारे तरीकों से उसमें कार्य किया जाता है। लेकिन खासतौर से जिनके लिये सिडबी द्वारा कार्य किया गया है, उनका यहां इसके अंदर मेंशन किया गया है । अगर आप इस बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं ।

सैयद सिब्ते रजी : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसे कि उनके उत्तर में कहा गया है कि गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को सहायता उपलब्ध कराता है । तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन से अन्य ऐसे प्रदेश है जहां इस प्रकार की सुविधायें आपने उपलब्ध करवाई है । पिछले तीन वर्षों के आंकड़े आपके क्या है ? क्या इसमें विशेष ब्याज में कमी करते हैं क्योंकि अति लघु उद्योग और लघु उद्योग लोगों को उठाने के लिये आप इस तरह की सहायता देते हैं तो वापसी की क्या स्थिति रही है ? पिछले तीन वर्षों में कितना धन आपको वापस मिला है, इस तरह की जो सहायता आपने दी है उससे ?

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो धन वापसी की बात पूछी है तो वास्तव में सिडबी जो भी ऋण देती है और उसके जो रेट आप रिकवरी होती है वह पुअर है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में रेट आफ रिकवरी 25 परसेंट है और ओवर-ड्यू 26 परसेंट है । असम के अंदर रेट आफ रिकवरी 21 परसेंट है और ओवर-ड्यू 74 परसेंट है । बिहार के अंतर रिकवरी 12 परसेंट है और ओवर-ड्यू 100 परसेंट है । दिल्ली के अंतर रिकवरी 44 परसेंट है और ओवर-ड्यू 48 परसेंट है । गुजरात के अंतर रिकवरी 33 परसेंट है और ओवर-ड्यू 65 परसेंट है। हरियाणा के अंतर रिकवरी 46 परसेंट है और ओवर-ड्यू 35 परसेंट है ।

MR. CHAIRMAN: This is a long list. Please send it...*(Interruptions)*...

DR. ABRAR AHMED: This is a list of recoveries. But the overall position is very, very poor.

MR. CHAIRMAN: I think you have given...*(Interruptions)*...

डा. अबरार अहमद : जहां माननीय सदस्य ने अन्य प्रदेशों को सहायता देने के लिये पूछा है सिडबी डाइरेक्ट किसी को भी सहायता नहीं देती है । वह रीफाइनेंसिंग करती है । वह स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन के माध्यम से, स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से रीफाइनेंसिंग करती है और उसकी स्कीमें सभी प्रदेशों के लिये है ।

श्री छोटू भाई पटेल : एट्थ फाईव यिअर प्लान में दस करोड़ लोगों को रोजगार देने का हमारा आयोजन है।

तो आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज बताई गई है, इन एक्टिविटीज से कितने लोगों को हम रोजगार दे पायेंगे और इस रोजगार में से रूरल एरिया में और स्पेसिफिकली ट्राइबल एरिया में कितना रोजगार हम दे पायेंगे ?

डा. अबरार अहमद : सर, यह बताना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार देंगे, क्योंकि कितने लोग इसके लिए आवेदन करते हैं और कितने लोग इस तरह से सहायता चाहते हैं, वह उस पर निर्भर करता है। लेकिन प्रयास यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को, जो भी सिडबी के माध्यम से रोजगार, चाहे उनको ऋण देकर के हो, स्माल-स्केल उद्योग के लिए उनकी मदद की जाती है ।

SHRI CHHOTUBHAI PATEL: The reply says: "This assistance has created employment opportunities in the State including the rural areas and tribal areas."

इसमें स्पेसिफिक कहा गया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं।

डा. अबरार अहमद: वह एम्पलायमेंट अपरचुनिटी के लिए तो है ही—जो ऋण दिया जा रहा है, मदद की जा रही है, उससे छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं। Definitely, it is for employment.

पर कितनी एम्पलायमेंट अभी दी जा सकती है, वह डिपेंड करता है कि कितनी आवश्यकता होती है कितने आवेदन-पत्र आते हैं—वह उस पर निर्भर करता है।

DR. NAUNIHAL SINGH: I find from the reply that there is no mention at all about the promotion of agro-industries in the rural areas of Gujarat. Will the hon. Minister inform us whether the Small-Scale Industries Development Bank of India has formulated any project for the promotion of agro-industries in Gujarat? If so, the details thereof may be provided.

डा. अबरार अहमद: सभापतिजी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, वह सीधे-सीधे इस प्रश्न के अंतर नहीं आती है लेकिन अगर कृषि से संबंधित कोई भी छोटे उद्योग हैं तो सिडबी उसके लिए ऋण देता है और वह जिस प्रकार का आवेदन आता है, उस पर निर्भर करता है।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Mr. Chairman, Sir, I want clarifications on two points. One is, when we talk of development, salt and Kutch, then, immediately, a logical mind thinks of Kargil. Does it imply that you are going to give your final sanction to the Kargil project on which you know the emotional feelings of the people of Gujarat? Secondly, the Salt Commission is based in Jaipur which has nothing to do with salt. Sixty per cent of salt comes from the region of Kutch in Gujarat. Would you give an assurance that you will move the headquarters of the Salt Commission from Jaipur to Kutch, which has been a very, very longstanding demand?

डा. अबरार अहमद: सर, मैं स्वयं राजस्थान से हूं और जयपुर से कोई चीज माननीय सदस्य गुजरात ले जाने के बारे में मुझसे आश्वासन लेना चाहते हैं। मैं यह आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, I seek your protection. My question was on two points. The Minister is from India and not from Rajasthan at the moment.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, upgradation of technology in salt-making concerns the indigenous industry. It has no bearing on the proposal, which the hon. Member is referring to, from the foreign investors. As regards the question of Salt Commission, the Ministry of Finance is not the agency which is concerned with the office of the Commissioner for Salt. That question should be put to the relevant Ministry.

*207. [*Transferred to 18th August, 1993.*]

Implementation of Kutir Jyoti Yojana

*208. SHRI SARADA MOHANTY:†

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the number of villages State-wise where the 'Kutir Jyoti Yojana' has been implemented; and

(b) what is the number of villages State-wise in country where this scheme is likely to be implemented.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Sarada Mohanty.